ISSN 2278-8808 SJIF 2014 = 4.889
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

भारत–पाक सम्बन्धों में आतंकवाद एवं संवाद का दौर शायद अब और नहीं

हेमन्त कुमार पाण्डे[1], Ph. D. & सुनीत कुमार चौबे[2], Ph. D.

[1]रीडर, रक्षा अध्ययन विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ (उत्तरप्रदेश)

[2]अतिथि शिक्षक, रक्षा एवं सामरिक अध्ययन केन्द्र, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)

Abstract

आज भारत–पाक सम्बन्धों में अविश्वास की एक ऐसी गहरी खाई बन गई है जिन्हें पाटना अब नामुमकिन सा लग रहा है क्योंकि जिस जहरीली मानसिकता के चलते जिहादी मुसलमानों ने तत्कालीन परिस्थितियों में सिर्फ पाकिस्तान लेकर अपने गुप्त योजना के तहत भारत का विभाजन किया था आज पाकिस्तान में ऐसी जेहादी सोच रखने वालों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वे अब अपने दबे–छुपे एजेंडे से बाहर आकर भारत में धीरे–धीरे आतंकवाद एवं अलगाववाद की गतिविधियों को खुलकर अंजाम दे रहे हैं और धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू एवं काश्मीर में आतंक एवं अलगाव का ऐसा कुचक्र चलाया है कि घाटी में कौन अपना है और कौन बेगाना, पहचानना मुश्किल हो गया है। आज न सिर्फ जम्मू–कश्मीर में आतंकी गतिविधियाँ लगातार जारी है अपितु सम्पूर्ण भारत में अब आतंकवाद का सिलसिला चल निकला है और कब और किस शहर में ये जेहादी इस्लामी आतंकवादी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जायेंगे यह सामान्य भारतीय जनमानस सोच भी नहीं सकता। जॉन हॉफकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ वाल्टर एंडरसन का कहना है कि – ''भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, आतंक के विरूद्ध युद्ध का समर्थन करता है और यहाँ आबादी में हिन्दू बहुसंख्यक हैं। ये सभी बातें इस्लामिक जेहादी आन्दोलन की दुश्मन मानी जाती है। इसलिए जेहादी गुट उस तरह काश्मीर की मांग नहीं कर रहे हैं। वे दरअसल, भारत के टुकड़े–टुकड़े कर देना चाहते हैं।''1 मई 2014 में भारत में नई सरकार के गठन के उपरांत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पाकिस्तान नीति में नाटकीय बदलाव आया। शुरुआती उत्साह से दिसम्बर 2015 में प्रधानमंत्री ने लाहौर की अचानक यात्रा करके पूरे विश्व समुदाय को यह बताने की कोशिश की कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को ठीक करने का पक्षधर है लेकिन एक ऐसे दौर में जब सारी दुनिया में आतंकवादी विरोधी माहौल अपने उत्कर्ष पर हो, बड़े से बड़े तीसमारखां आतंकवादी सरगना दुम–दबाकर भाग रहे हों, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढेर किया जा चुका हो तब भी भारत घुटभैये आतंकवादियों के लिए भी सबसे पसंदीदा निशाना बन रहा हो, यह चिन्ता की नहीं, बल्कि लज्जा की बात है। यह भारत की निहायत नरम और सहिष्णु छवि का भी खामियाजा है, जो आतंकवादियों को अक्सर आकर्षित करती रही है। यह छवि एक दिन में नहीं बनी है बल्कि लगभग दो दशकों से ज्यादा समय से देश पर लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों के बाद उनसे निपटने के हमारे दिखावटी और शिथिल संकल्पों से बनी है। जब भी कोई आतंकी वारदात होती है तो थोड़ी देर के लिए वीररस से सने वक्तव्यों की बाढ़ जरूर आती है लेकिन जल्दी ही घटना की जवाबदेही को लोकतांत्रिक ढंग से इधर–उधर सरकाकर हमारे हुक्मरान अपने काम–काज में लग जाते हैं और देश अगली वारदात की प्रतीक्षा करने लगता है।2 हम आजतक आतंकवाद के वास्तविक कारणों को पहचानने और उसके मूल स्रोतों पर मर्मांतक प्रहार करने की किसी सुविचारित योजना पर अमल की। हिम्मत नहीं जुटा सके हैं। इसलिए जुलाई 2015 में गुरदासपुर आतंकी हमले के उपरांत नई सरकार के सम्मुख पुनः वही पुरानी चुनौती आ गई है कि वह पाकिस्तान के साथ अब आतंकवाद एवं संवाद की स्थिति को समाप्त कर दूरदर्शिता के साथ साहस करते हुए देश–विदेश जहाँ से भी ये आतंकवादी हमले प्रेरित प्रायोजित हो रहे हैं उन अड्डों को तहस–नहस कर देना चाहिए।3

मुख्य शब्द *– आतंकवाद, भारत–पाक सम्बन्ध, जम्मू–काश्मीर घुसपैठ, जेहादी संगठन।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना –

पाकिस्तान के सन्दर्भ में भारत की विदेशनीति का लक्ष्य हमेशा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना रहा है परन्तु भारत के लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौती पड़ौसी राष्ट्र पाकिस्तान से बिगड़े सम्बन्धों को सुधारने की रही है।4 भारत ने जब–जब पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने का प्रयास किया है तब–तब पाकिस्तान ने हमें न सिर्फ धोखा दिया है अपितु भारत को रक्तरंजित करने का हर सम्भव प्रयास किया है। काश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देने के सन्दर्भ में पाकिस्तान की नीति यह है कि यहाँ आजादी की लड़ाई चल रही है और वह इस लड़ाई का नैतिक समर्थन करता है जबकि वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवादियों को सहायता, शरण और समर्थन देता रहा है अपितु उनकी उत्पत्ति ही पाकिस्तानी मदरसों, सरकारी स्कूलों में हुई है जिन्हें पालपोस कर वह भारत के खिलाफ प्रयोग कर रहा है। किसी आतंकी वारदात के उपरांत जब पाकिस्तान पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव पड़ता है तो वह आतंकवादियों के खिलाफ कुछ दिखावटी कदम उठा लेता है और कुछ समय पश्चात फिर उन्हीं क्रियाकलापों में संलग्न हो जाता है। वास्तव में इस्लामिक जेहादियों को कुछ समय के लिए शांत करके रखना और फिर उन्हें आतंक मचाने की खुली छूट देना, पाकिस्तानी प्रतिष्ठान की पुरानी रणनीति है। वर्ष 2003 में हेराल्ड में छपी एक खबर के मुताबिक पूर्व भातीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वापपेयी के श्रीनगर पहल से खिन्न जिहादियों के संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की मुजफ्फराबाद में बंद कमरे में हुई एक बैठक में भविष्य में उठाये जाने वाले कदमों के बारे में विचार किया गया। इस बैठक में पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया जिन्हें यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने 'बड़े नीतिगत बदलाव' के खिलाफ चेतावनी दे रखी थी। जेहादी संगठन के नजदीकी सूत्रों का हवाला देते हुए अखबार लिखता है कि वे पाक अधिकृत काश्मीर के अधिकारियों से यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 'हमारे दृष्टिकोण को सुनो और उस पर सहमति व्यक्त करो कि हमारे कार्यालय बन्द नहीं होने चाहिए। परन्तु पीओके के सरकारी अधिकारियों की जिहादियों से यह मांग है कि वे कोई Public Statement नहीं देंगे, कार्यालयों में हथियारों का प्रदर्शन या किसी अनावश्यक गतिविधियों को अंजाम नहीं देंगे। वे जेहादियों को जोर देते हुए यह सलाह भी देते हैं कि उनके अगले आदेश तक, सीमापार की गतिविधियों की योजना न बनाई जाए।'5

यद्यपि छल–कपट की कोई सीमा नहीं है चाहे वह आतंकी अड्डों को स्थानान्तरित करने की बात हो या फिर जिहादियों से थोड़ी देर शांत रहने और फिर तूफानी गति से मौत के व्यापार को चालू करने की बात हो। पाकिस्तान जानबूझ कर भारत में इस प्रकार के आतंकी हमलों को अंजाम दिलवाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि प्रत्यक्ष युद्ध में वह भारत से पार नहीं पा सकता इसलिए वह छद्म आतंकवाद का सहारा लेता है। लश्करे तैयबा के नेता हाफिज सईद लगातार पाकिस्तान का

पसंदीदा बना हुआ है क्योंकि वह न सिर्फ अपने जिहादी संगठन पर पूर्ण नियंत्रण बनाए हुए है अपितु इसलिए भी कि वे पाकिस्तान में स्थापित किसी भी सरकार या प्रतिष्ठान के खिलाफ नहीं हैं किन्तु यह निश्चित रूप से लश्करे तैयबा को एक खतरनाक संगठन बनाता है। पाकिस्तानी पत्रकारों के अनुसार लश्कर, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा विस्तृत आतंकी संगठन है और इसकी शक्ति दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्हें भय है कि लश्करे तैयबा आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए भयंकर चुनौती खड़ी करेगा।6

मोदी सरकार के गठन के पश्चात् भारत–पाक सम्बन्ध :

भारत–पाक सम्बन्धों में महत्त्वपूर्ण बदलाव आने के संकेत देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंकवाद और संवाद साथ–साथ नहीं चल सकता। पूर्ववर्ती सरकारों ने जितना संयम और सहनशीलता का प्रदर्शन अब तक किया है शायद अब उस प्रकार की नीति इस सरकार में देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय गृह मंत्रालय ने कहा कि गुरदासपुर में 27 जुलाई 2015 में किया गया हमला लश्कर–ए–तैयबा ने अंजाम दिया है। आतंकवादियों द्वारा GPS सिस्टम का उपयोग करते हुए पाकिस्तानी सीमा से भारत में प्रवेश किया गया जो यह संकेत देता है कि अब आतंकवादी आधुनिक संचार तंत्र का बखूबी प्रयोग करने लगे हैं जैसा कि मुम्बई हमले के दौरान भी देखने को मिला था।7 गुरदासपुर हमला लश्कर–ए–तैयबा के पुनः सक्रिय होने का संकेत देते हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अब मोदी–डोभाल सिद्धांत आतंक के इस स्रोत से कैसे निपटेगा। हालांकि गुरदासपुर हमला पंजाब में सिख उग्रवाद के पुनरुत्थान के रूप में देखा जाने वाला एक उपर्युक्त मामला नहीं हो सकता फिर भी राज्य में एक लम्बे अंतराल के बाद आतंकवादी हमला चिन्ता का कारण बन जाता है। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि पाकिस्तान अभी भी बहुत उत्साह से खालिस्तान समर्थक तत्त्वों की अच्छी संख्या की मेजबानी करता है।8 गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच यदि अब कोई बात होगी तो वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी, अन्य किसी भी मसले पर बात नहीं होगी।

यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने पाकिस्तान से इतनी स्पष्ट भाषा में बात की होती तो शायद हमें आतंक के इतने घाव न झेलने पड़ते परन्तु अफसोस कि अभी तक की सरकारें सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय वाहवाही के चक्कर में राष्ट्रीय हितों की बलि देती रही हैं। वास्तव में संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले के पश्चात भारत के पास एक सुनहरा अवसर था कि पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर उसकी भूमि पर पल रहे आतंकवादियों और आतंकी शिविरों को नष्ट कर दे परन्तु सेना की तमाम तैयारियों के बावजूद तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व कोई कठोर फैसला न कर सका और पाकिस्तान के हौंसले लगातार बढ़ते रहे। जम्मू–कश्मीर में आतंकवादियों के दुस्साहस का दमन इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि न तो सीमापार से उनकी घुसपैठ रोकने में सफलता मिल पा रही है और न ही स्थानीय

स्तर पर उनके समर्थकों एवं संरक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। यही कारण है कि इस राज्य में आतंकवाद की कमर नहीं टूट रही। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार इस तथ्य से परिचित न हों कि आतंकवादियों को कहाँ शरण मिलती है और कौन लोग उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं, लेकिन समस्या यह है कि ऐसे तत्त्वों के प्रति जरुरत से ज्यादा नरमी का परिचय दिया जा रहा है। यदि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों का सफाया नहीं कर पा रही है तो यह कहना कि वह अपने बलबूते आतंकवाद को परास्त करने में सक्षम है, समझ से परे है। अमेरिका में 11 सितम्बर 2001 की आतंकी घटना के पश्चात् आज तक आतंकवादी वहाँ कोई भी हिंसक वारदात नहीं कर सकते हैं, फिर भारत ही बार–बार इस विष को पीने के लिए अभिशप्त क्यों है? जाहिर है आतंकवाद एवं उसके स्रोतों पर निर्मम और निर्णायक प्रहार करने से अभी तक बचा गया है। क्या यह राष्ट्रीय चिन्ता का विषय नहीं बनना चाहिए कि केन्द्र सरकार आतंकवाद से लड़ने के प्रति जितनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है,

आतंकी संगठन उतना ही बेलगाम और बेखौफ होते जा रहे हैं। इससे भी खतरनाक यह है कि वे स्थानीय स्तर पर हर तरह का सहयोग हासिल करने में भी समर्थ है। निश्चित रूप से इसके लिए कहीं न कहीं केन्द्र व राज्यों की नीतियाँ उत्तरदायी हैं। विडम्बना यह है कि आतंकवाद के प्रति ढुलमुल नीतियों के मूल कारण वोट बैंक की राजनीति में निहित नजर आते हैं।9

आज भारत–पाक सम्बन्धों में हम जिस आतंकवाद की चर्चा इतने दिनों से करते आये हैं वह नव आतंकवाद मजहबी खोल ओढे हुए है और इस चुनौती का मुँहतोड़ जवाब हम देने में पूरी तरह सक्षम हैं, परन्तु आतंकवादी चुनौती तब लोहे–सी लगने लगती है जब इसको मात देने के लिए कुछ विशेष करने की बजाय कुछ लोग, जो कुछ किया जाता है, उस पर भी पानी फेरने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश के सीने में कटार भोंक रहे इन दुश्मनों के साथ रियायत बरतना ही हमारी धर्मनिरपेक्षता है। हम बार–बार धोखा खाने के बावजूद यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि पाकिस्तान एक न एक दिन सुधर जायेगा और आतंकवाद एवं अलगाववादी गतिवधियों को समाप्त कर हमसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लगेगा। शायद हम भूल गये हैं कि जिस पाकिस्तान का निर्माण ही हिन्दू विरोधी मानसिकता के चलते हुआ है वह इस्लामिक राज्य पाकिस्तान तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वह भारत का पूर्ण इस्लामीकरण न कर दे। हमारी नवगठित मोदी सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को आगे बढ़ाने पर विचार करते समय इस मूल तथ्य को सदैव अपने ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी हमारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता और यदि अब पाकिस्तान ने भारत में एक भी आतंकी हमले को अंजाम दे तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाय कि उसे यह अहसास हो जाए कि अब भारत पाकिस्तान के किसी भी आतंकी हमले का मुँहतोड़ जवाब देगा जो कि अभी तक नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती दौर में ही पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने और दोनों

राष्ट्रों के मध्य व्याप्त अविश्वास को दूर करने के लिए काफी ऊर्जा व पूंजी का निवेश किया था। अन्य बातों के अलावा, इन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ को 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया और दिसम्बर 2015 में पाकिस्तान का अचानक दौरा भी किया जिसका मकसद सिर्फ दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सुधारना था।10 परन्तु पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत की पीठ में छूरा घोंपने से बाज नहीं आ रहा है जिसका नतीजा पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों को भुगतना पड़ेगा।

दरअसल भारत–पाक सम्बन्धों में पाकिस्तान का भारत के प्रति शत्रुभाव का मूल कारण वह इस्लामी सिद्धान्त और विचारधारा है, जिसके आधार पर मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन करने और इसकी प्राकृतिक सीमाओं के अन्तर्गत एक अलग इस्लामी राज्य बनाने की मांग उठाई थी। मिल्लत और कुफर, दार–उल–इस्लाम और दार–उल–हरब के इन सिद्धान्तों के अनुसार पाकिस्तान दार–उल–इस्लाम है। उसका यह मजहबी कर्त्तव्य है कि वह खण्डित भारत, जो इन सिद्धान्तों के अनुसार दार–उल–हरब है, को दार–उल–इस्लाम बनाने के लिए इसके विरुद्ध सतत् प्रयास करे।11 पाकिस्तान हमेशा इन्हीं सिद्धान्तों पर चलता रहा है और वह मूर्ख भी नहीं है, कम से कम रणनीतिक मामलों में उसकी महत्त्वाकांक्षा भारत के रुख को देखकर ही बढ़ी है और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का आचरण भांप कर ही वह अपनी नीतियों पर कायम है।12 शांति, अहिंसा व दोस्ती के नाम पर 'आस्तीन के सांप' को गले में लपेट कर रखना सांप की नहीं वरन् हमारी गलती है। यदि हम समय रहते नहीं चेते तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान, भारत को पुनः संसद भवन जैसे हमलों से रक्तरंजित कर दे और हमारे शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का ही सफाया कर दे।

हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान जब भी कोई वार्ता शुरू करता है तो उसका एक ही तर्क होता है कि काश्मीर में रहने वाले बहुसंख्यक मुसलमान हैं इसलिए वह उसके कब्जे में होना चाहिए और केवल इसी बात को लेकर वह हमसे चार बार युद्ध कर चुका है। हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि विश्व की कुछ ताकतें हमारी राष्ट्रीय सम्प्रभुता और अखंडता की कीमत पर पाकिस्तान से समझौता कराने का षड्यंत्र कर रही हैं। इसके पीछे कुछ उनके हित हैं तो कुछ उनकी आशंकाएं। इन्हीं आशंकाओं में एक आशंका परमाणु युद्ध की है। इसका सच यह है कि विश्व बिरादरी और विश्व शांति को खतरा भारत से नहीं, पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक जेहादियों एवं उसके आतंकी नेटवर्क से है। दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध के खतरे की बार–बार बात करना इसी भयादोहन का अंग है। पाकिस्तानी शासक हमेशा इस बात का प्रचार करते हैं कि यदि काश्मीर समस्या का समाधान उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ तो दोनों देशों के मध्य परमाणु युद्ध भी भड़क सकता है।13 वास्तव में यह पाकिस्तान की एक चाल है कि जब शांति की बातें उसके अनुकूल न हों तो भारत को आतंकवादी हिंसा या परमाणु युद्ध के जरिये विचलित किया जाये, परन्तु पाकिस्तान

को अब यह समझ लेना चाहिए कि आज भारत में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली पूर्ण बहुमत की प्रखर राष्ट्रवादी सरकार है जो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने में सक्षम है।

निष्कर्ष एवं सलाह –

भारत–पाक सम्बन्धों में आज जो गिरावट का दौर दिख रहा है उसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह जिम्मेदार है क्योंकि वह आतंकवाद और संवाद की स्थिति को बनाए रखकर भारत को लगातार उलझाये रखना चाहता है। यदि भारत कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की स्थिति में नहीं है तो फिर उसे ऐसे अन्य उपायों को आजमाने में देर नहीं करनी चाहिए जो पाकिस्तान को भारत विरोधी नीति का परित्याग करने के लिए विवश करे।

पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान अपनी जनता को हमेशा एक ही बात रटाता रहा है कि काश्मीर में हो रही हिंसा के लिए भारत जिम्मेदार है और वह हमारे भाई–बन्धुओं पर काश्मीर में अत्याचार कर रहा है। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वहाँ की सेना के जनरलों ने सदैव काश्मीर के मुद्दे को हवा देकर वहाँ की अंदरूनी घृणा और जातीय वैमनस्य को नियंत्रित करने की कोशिश की है। वास्तव में पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं बल्कि इतिहास की एक दुर्घटना द्वारा साथ रहने को मजबूर की गई एक भीड़ है। पाकिस्तान कभी एक राष्ट्र नहीं रहा है। यह असहिष्णु एवं लड़ाकू जातियों का जमघट है और शासन एवं सेना दोनों में पंजाबियों का वर्चस्व रहा है। पाकिस्तान की जनसंख्या में वे लगभग 60 प्रतिशत, सिन्धी लगभग 20 प्रतिशत, पख्तून 10 प्रतिशत, बलूच 5 प्रतिशत और उर्दू भाषा–भाषी मुहाजिर लगभग 7 प्रतिशत है।14 पाकिस्तानी सोच चाहे जो भी हो हमें यह बात अपने दिलो–दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेनी चाहिए कि भारत–पाक सम्बन्धों को मधुर बनाने की चाहे हम लाख कोशिश कर लें लेकिन दोनों देशों के सम्बन्ध कभी भी सामान्य नहीं हो सकते क्योंकि पाकिस्तान का मूल मकसद भारत के अस्तित्व को समाप्त कर यहाँ इस्लामिक शासन कायम करना है। यह आजमाया हुआ तथ्य है कि पाकिस्तान काश्मीर समस्या का कोई शांतिपूर्ण समाधान निकलने नहीं देगा क्योंकि उसका खेल तो कुछ और ही है जो जम्मू–काश्मीर के बहाने खेला जा रहा है। यदि भारत समय रहते इन इस्लामिक जेहादी ताकतों को कुचलने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाता है तो फिर वह अपना अस्तित्व शायद ही बचा पायेगा इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

सन्दर्भ –

India Today - 8 December 2003, P-37
Hindustan- 14 December 2001
The Times of India - 14 December 2001, P.1
Pratiyogita Darpan - May 2010, P-1826
Dr. Ved Kishore 'Ratudi', Failed Indian Foreign Policy in the Context of Pakistan.
Herald - July 2003, P-13

Sushant Sareen, 'The Jihad Factory: Pakistan's Islamic Revolution in the Making, Observer Research Foundation in association with Har-Anand Publication Pvt. Ltd. New Delhi,2005,P-88

Gurdaspur Terrer attack : GPS shows terror team from Pakistan, got help from drug cartel too, The Indian Express - 28 July 2015

Rajeev Sharma : India News - 30 July 2015, 09:03:32 IST

Dainik Jagran - 13 July 2006, P-10

The Times of India - 29 December 2015

Pratiyogita Darpan - April 2005, P-1650

Shankar Shran, Tragedy of Kashmiri Pandits, Dainik Jagran - 3 April 2003, P-10

Bhanupratap Shukla, Journey of Struggle and dialogue, Dainik Jagran - 2 June 2003, P.10

Dainik Jagran - 8 December 2002, P-10